



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दोषमुक्ति अपील सं 449/2024

1 - जूली भंसाली पति श्री प्रेमचंद भंसाली, आयु लगभग 45 वर्ष दौंडिलोहरा, तहसील दौंडिलोहरा, जिला बालोद (सी. जी.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 - संजय सिंघी पिता श्री टी. सी. सिंघी, आयु पिता 50 वर्ष, निवासी वर्धमान नगर, वार्ड संख्या 17, राजनंदगांव, तहसील तथा जिला राजनंदगांव (सी. जी.)

---उत्तरवादी

याचिकाकर्ता हेतु:--श्री बी. पी. सिंह, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु:--अधिवक्ता श्री रवि कुमार बोधानी, अधिवक्ता श्री आशीष गंगवानी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।

माननीय श्री नरेन्द्र कुमार व्यास, न्यायाधीशपीठ पर आदेश

13.02.2025

1. अपीलार्थी/परिवादी ने विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डौंडिलोहरा, जिला बालोद (छ.ग.) द्वारा पारित दिनांक 13.03.2023 के आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(4) के तहत वर्तमान दोषमुक्ति अपील दायर की है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/परिवादी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में "एनआई अधिनियम, 1881") की धारा 138 के तहत दायर परिवाद को खारिज कर दिया है।

2. अभिलेख से परिलक्षित संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलार्थी/परिवादी ने विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डौंडिलोहरा, जिला बालोद (छ.ग.) के समक्ष धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत परिवाद दर्ज कराई है,



जिसमें आरोप लगाया गया है कि परिवादी ने लिखित वचन पत्र के निष्पादन के बाद 28.11.2017 को अभियुक्त को 6,00,000/- रुपये दिये थे, जिसमें उल्लेख था कि वह 25.02.2018 तक राशि वापस कर देगा तथा 6,00,000/- रुपये की उक्त ऋण राशि पर 1.50 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देने का भी वादा किया था। वचन पत्र के अनुपालन में अभियुक्त ने 09.03.2020 तक ब्याज का भुगतान किया है तथा उसके बाद ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया था। जब परिवादी ने राशि की मांग की, तो उत्तरवादी ने भारतीय बैंक, शाखा राजनांदगांव के साथ बैंक खाता संख्या SB938591305 में 6,00,000/- रुपये का चेक दिया, जिस पर चेक संख्या 027595 दिनांक 18.08.2022 अंकित है। अपीलकर्ता/परिवादी ने इसे बैंक में जहां वह खाता रखता है, 05.09.2022 को जमा किया, जिसे अनादरित कर दिया गया और 09.09.2022 को परिवादी को अग्रेषण ज्ञापन में यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि 'अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित हुआ, इसके बाद, परिवादी ने 10.10.2022 को एक कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब दायर नहीं किया गया है। दिनांक 10.10.2022 का वही नोटिस अभियुक्त को विधिवत तामील किया गया था, लेकिन उसने न तो इसका जवाब दिया और न ही राशि का भुगतान किया, जिसके कारण परिवादी को 29.11.2022 को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद दर्ज कराने की आवश्यकता पड़ी, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने 13.03.2023 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया कि बैंक द्वारा परिवादी को चेक अग्रेषण ज्ञापन 09.09.2022 को संप्रेषित किया गया था और नोटिस 10.10.2022 को जारी किया गया है, अर्थात् 30 दिनों के बाद। इस प्रकार, इसने इस आधार पर परिवाद को खारिज कर दिया है कि यह 30 दिनों के बाद तामील किया गया है जो एनआई अधिनियम की धारा 138 (बी) का उल्लंघन है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आक्षेपित आदेश विकृत और अवैध है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता 10.09.2022 से सीमा की गणना करने का हकदार है, जो कि एनआई अधिनियम की धारा 105 के अनुसार अग्रेषण ज्ञापन प्राप्त करने की अगले दिनांक 09.09.2022 है, जो यह प्रावधान करती है कि 30 दिनों की अवधि की गणना से अवकाश को अपवर्जित रखा जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि सीमा की अगली तारीख 09.09.2022 से ही शुरू होगी, जबकि यह 10.10.2022 को दी गई है, इस प्रकार यह सीमा द्वारा वर्जित है और उन्होंने कहा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने शिकायत को खारिज करने में कोई अवैधता नहीं की है। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए वह **कमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए, जिसकी रिपोर्ट LAWS(SC) 2013 1223 में दी गई है, जिसमें कंडिका 12 से 14 इस प्रकार है:---

“12. वर्तमान मामले में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि चेक दूसरी बार 10.11.2008 को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, परिवादी ने 17.12.2008 को कानूनी नोटिस भेजा, यानी 30 दिनों की समाप्ति के काफी बाद। परिवादी द्वारा स्वयं दायर किया गया परिवाद से यह स्पष्ट है कि वह 10.11.2008 को



चेक भुनाने के लिए बैंक गया था, लेकिन खाते में शेष राशि न होने के कारण चेक का भुगतान नहीं किया गया था।

13. महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि परिवादी को चेक के अनादर के बारे में सूचना किस दिनांक को मिली। अपीलकर्ता के अनुसार परिवादी को चेक के अनादर के बारे में सूचना 10.11.2008 को मिली। हालांकि, उत्तरवादी ने इस पर विवाद किया है। हालांकि, हम यह जोड़ना चाहते हैं कि बहस के समय अपीलकर्ता के उपरोक्त प्रस्तुतीकरण का खंडन नहीं किया गया था। निर्णय सुरक्षित रखे जाने के पश्चात, परिवादी ने शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसे चेक बाउंस होने का बैंक मेमो 17.11.2008 को प्राप्त हुआ था, तथा इसलिए 17.12.2008 को भेजा गया विधिक नोटिस सूचना की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर है। सामान्यतः, हम पक्षों को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करके ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने-अपने कथनों को सिद्ध करने के लिए कहते हैं। हालांकि, वर्तमान प्रकरण में, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सही रूप से इंगित किया है, परिवादी ने परिवाद में ही स्वीकार किया है कि वह 10.11.2008 को चेक भुनाने के लिए बैंक गया था, तथा धनराशि अपर्याप्त होने के कारण चेक का भुगतान नहीं किया गया, जिससे यह स्वीकार किया जा सके कि उसे 10.11.2008 को ही चेक के अनादर के बारे में पता चला था। यही कारण है कि अपीलकर्ता ने जवाबी शपथ पत्र दायर किया है जिसमें कहा गया है कि यह एक बाद में विचार किया गया तथा तर्क यह है क्योंकि विचारण न्यायालय के समक्ष कोई भी सामग्री दायर नहीं की गई है जिससे पता चले कि बैंक ने चेक की वापसी के बारे में ज्ञापन जारी किया था जो परिवादी को 17.11.2008 को प्राप्त हुआ था। इस संबंध में परिवाद में किया गया विशिष्ट कथन इस प्रकार है:

“इसके बाद परिवादी फिर से 10.11.2008 को अभियुक्त द्वारा दिए गए चेक को भुनाने गया जो अभियुक्त के खाते में शेष राशि की अनुपलब्धता के कारण फिर से बाउंस हो गया।”

इस प्रकार, परिवादी द्वारा स्वयं दिए गए उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वह 10.11.2008 को चेक भुनाने के लिए बैंक गया था और पाया कि खाते में पर्याप्त शेष राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया था। इसलिए, यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे 10.11.2008 को ही इसके बारे में पता चला था। परिवाद में इस स्वीकारोक्ति के तहत कि परिवादी को चेक बाउंस होने के बारे में 10.11.2008 को ही जानकारी मिल गई थी, इस पहलू पर आगे कोई जांच की आवश्यकता नहीं है।

14. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उसे चेक के अनादर के बारे में 10.11.2008 को ही जानकारी मिल गई थी। हालांकि, उसने 30 दिनों के भीतर विधिक नोटिस नहीं भेजा। इस प्रकार, हम पाते हैं कि उनके द्वारा दायर की गई परिवाद विचारणीय नहीं थी क्योंकि यह एन. आई. अधिनियम की धारा 138 में निर्धारित समस्त तीन शर्तों को पूरा किए बिना दायर की गई थी, जैसा कि ऊपर निकाले गए एम. एस. आर. चमड़ों के मामले में निर्णय के कंडिका 12 में समझाया गया है।”

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेखों का अवलोकन किया है।



6. पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों से यह निर्धारित करने के लिए बिंदु उभर कर आते हैं:

(i) क्या परिसीमा अवधि 10.09.2022 से शुरू होगी या 09.09.2022 से तथा

(ii) क्या अपीलकर्ता 30 दिनों की गणना के लिए रविवार यानी 09.10.2022 को अपवर्जित करने का हकदार है?

7. इस बिंदु को समझने के लिए, इस न्यायालय के लिए एन.आई. अधिनियम की धारा 105 और 138 के साथ-साथ सामान्य खंड अधिनियम की धारा 9 और 10 को उद्धृत करना समीचीन है, जो इस प्रकार है:

“105 युक्तियुक्त समय – स्वीकृति या भुगतान के लिए प्रस्तुत करने, अनादर की सूचना देने और नोट करने के लिए उचित समय निर्धारित करने में, लिखत की प्रकृति और समान लिखतों के संबंध में व्यवहार के सामान्य तरीके को ध्यान में रखा जाएगा; और ऐसे समय की गणना करते समय सार्वजनिक अवकाश को शामिल नहीं किया जाएगा।

138. खाते में निधियों की अपर्याप्तता आदि के कारण चेक का अनादर।:-----

जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या आंशिक रूप से उन्मोचन के लिए उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को धनराशि के भुगतान के लिए बैंक में अपने द्वारा खोले गए खाते पर निकाला गया कोई चेक बैंक द्वारा बिना भुगतान के वापस कर दिया जाता है, या तो इसलिए कि उस खाते में जमा धनराशि चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या यह उस बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली धनराशि से अधिक है, ऐसे व्यक्ति को अपराध करने वाला समझा जाएगा और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे दो वर्ष तक की अवधि के कारावास या चेक की धनराशि के दुगुने तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा; परंतु कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि—

(क) चेक बैंक को उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, जिसको वह निकाला गया

(ख) चेक का प्राप्तकर्ता या धारक, जैसा भी मामला हो, चेक के लेखक को लिखित में नोटिस देकर उक्त धनराशि के भुगतान की मांग करता है, [चेक के अवैतनिक रूप से वापस आने के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर; और

(ग) ऐसे चेक का लेखक, उक्त नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, चेक के लेखक को, जैसा भी मामला हो, प्राप्तकर्ता या धारक को उक्त धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है।”

8. सामान्य खंड अधिनियम की धारा 9 तथा 10 निम्नानुसार है:

“9. समय का प्रारंभ और समाप्ति – (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात बनाए गए किसी केन्द्रीय अधिनियम या विनियमन में, दिनों की श्रृंखला या किसी अन्य समयावधि में प्रथम को बाहर करने के प्रयोजन के



लिए, "से" शब्द का प्रयोग करना पर्याप्त होगा, तथा दिनों की श्रृंखला या किसी अन्य समयावधि में अंतिम को सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए, "तक" शब्द का प्रयोग करना पर्याप्त होगा।

(2) यह धारा 3 जनवरी, 1868 के पश्चात बनाए गए सभी केन्द्रीय अधिनियमों और 14 जनवरी, 1887 को या उसके पश्चात बनाए गए सभी विनियमों पर भी लागू होती है।

10. समय की गणना – (1) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात बनाए गए किसी केन्द्रीय अधिनियम या विनियमन द्वारा किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी निश्चित दिन या विहित अवधि के भीतर कोई कार्य या कार्यवाही किए जाने का निर्देश या अनुज्ञा दी जाती है, वहां यदि न्यायालय या कार्यालय उस दिन या विहित अवधि के अंतिम दिन बंद हो, तो कार्य या कार्यवाही को सम्यक् समय में किया गया या की गई समझा जाएगा, यदि वह उसके पश्चात् अगले दिन किया गया या की गई हो, जिस दिन न्यायालय या कार्यालय खुला हो: परन्तु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही पर लागू नहीं होगी, जिस पर भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1877 (1877 का 15) लागू होता है।

(2) यह धारा चौदह जनवरी, 1887 को या उसके पश्चात बनाए गए सभी केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों पर भी लागू होती है।"

9. धारा 138 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बैंक से मेमो की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर नोटिस दिया जाना चाहिए। निर्विवाद रूप से, मेमो 09.09.2022 को प्राप्त हुआ था और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 9 और 10 के अनुसार 09.09.2022 को 30 दिनों की अवधि की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए। यह विवाद्यक और एकीकृत नहीं है क्योंकि माननीय न्यायालय ने साकेत इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड के मामले में (1999) 3 एससीसी 1 में कंडिका 6 से 8 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है: 6. इसी प्रकार के तर्क पर इस न्यायालय ने हारु दास गुप्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1972) 1 एससीसी 639 के मामले में विचार किया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह नियम अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां किसी निश्चित तिथि से एक विशेष समय दिया गया है जिसके भीतर कोई कार्य किया जाना है, उस दिन के दिन को छोड़ दिया जाएगा; ऐसे दिन से लेकर ऐसे दिन तक की अवधि को परिभाषित करने का प्रभाव, जिसके भीतर कोई कार्य किया जाना है, पहले दिन को छोड़ देना और अंतिम दिन को शामिल करना है। उस मामले के संदर्भ में, न्यायालय ने माना कि नजरबंदी की तारीख से तीन महीने की अवधि की गणना करते समय, जो 5-2-1971 थी, जिसके समाप्त होने से पहले नजरबंदी आदेश की पुष्टि करने और उसके तहत नजरबंदी जारी रखने का आदेश या निर्णय किया जाना था, नजरबंदी के प्रारंभ की तारीख, अर्थात् 5 फरवरी को छोड़ दिया जाना चाहिए; ऐसा करने पर, 5-5-1971 का पुष्टि आदेश नजरबंदी की दिनांक से तीन महीने की अवधि की समाप्ति से पहले किया गया था। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि निर्माण के उपरोक्त नियम का लगातार और इतने लंबे



समय तक पालन न किया जाए।उपरोक्त सिद्धांत के लिए, न्यायालय ने अंग्रेजी न्यायालयों में अपनाए गए सिद्धांत का उल्लेख किया।सुसंगत चर्चा यहाँ नीचे दी गई है:

"5.इन निर्णयों से पता चलता है कि न्यायालयों ने किसी कार्य को करने के लिए निर्धारित अवधि और किसी कार्य को करने के लिए सीमित समय के बीच अंतर किया है। यह नियम सुस्थापित है कि जहां किसी निश्चित तिथि से एक विशेष समय दिया गया है जिसके भीतर कोई कार्य किया जाना है, उस तिथि को उस दिन को छोड़ दिया जाना चाहिए।(गोल्डस्मिथ्स कंपनी बनाम वेस्ट मेट्रोपॉलिटन आर. एल. कं.:1904 1 पी पर के. बी. 1,5 के. बी.5.)इस नियम का पालन कार्टवराइट बनाम मैककॉर्मेक में किया गया था:(1963) 1 समस्त ई. आर. 11,13:पी पर समस्त ईआर।13, जहां बीमा कंपनी द्वारा जारी कवर नोट में 'पॉलिसी के शुरू होने से पंद्रह दिन' की अभिव्यक्ति को पहली तारीख और उस दिन की आधी रात को शुरू होने वाले कवर नोट को छोड़कर समझा गया था, और मैरेन बनाम डॉसन बेंटले एंड कंपनी लिमिटेड, (1961) 2 क्यूबी 135 में, रोजगार के दौरान प्राप्त चोटों के लिए मुआवजे का मामला, जहां सीमा की अवधि की गणना के प्रयोजनों के लिए दुर्घटना की तारीख, कार्रवाई के कारण की तारीख को बाहर रखा गया था। (स्टीवर्ट बनाम चैपमैन (1951) 2 केबी 792 और नॉर्थ, रे, एक्स पी हैसलक (1895) 2 क्यूबी 264 भी देखें।)इस प्रकार, एक सामान्य नियम के रूप में ऐसे दिन से ऐसे दिन तक की अवधि को परिभाषित करने का प्रभाव है जिसके भीतर एक कार्य किया जाना है, पहले दिन को बाहर करना तथा अंतिम दिन को शामिल करना है।[हैल्सबरीज लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, (तीसरा संस्करण) Vo1.37, पीपी।92 तथा 95।]कोई कारण नहीं है कि निरंतर और इतने लंबे समय तक पालन किए जाने वाले निर्माण के उपरोक्त नियम को यहां भी लागू नहीं किया जाना चाहिए।"

7. जिस दिन से अवधि की गणना की जानी है, उसे बाहर करने का उपरोक्त सिद्धांत सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12(1) और (2) में शामिल किया गया है। धारा 12(1) में विशेष रूप से प्रावधान है कि किसी भी वाद, अपील या आवेदन के लिए सीमा की अवधि की गणना करते समय, जिस दिन से ऐसी अवधि की गणना की जानी है, उसे अपवर्जित रखा जाएगा। अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए उप-धारा (2) में समान प्रावधान किया गया है।यही सिद्धांत साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 में भी शामिल किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि साधारण खंड अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाए गए किसी भी केंद्रीय अधिनियम में, दिनों की श्रृंखला या किसी अन्य समयावधि में पहले दिन को छोड़ने के प्रयोजन के लिए 'से' शब्द का प्रयोग करना पर्याप्त होगा, और दिनों की श्रृंखला या किसी अन्य समयावधि में अंतिम दिन को सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए 'तक' शब्द का प्रयोग करना पर्याप्त होगा।

8. इसलिए, उपरोक्त मामले में प्रतिपादित नियम को न अपनाने का कोई कारण नहीं है, जिसका लगातार पालन किया जाता है और जिसे साधारण खंड अधिनियम और परिसीमा अधिनियम में अपनाया गया है। आमतौर पर समय की गणना करने में, पालन किया जाने वाला नियम पहले दिन को छोड़ने और अंतिम दिन को शामिल करने का है।उक्त नियम को लागू करते हुए, शिकायत दर्ज करने के लिए एक महीने की अवधि की गणना उस दिन से की जाएगी जिस दिन नोटिस प्राप्त करने वाले द्वारा 15 दिनों की अवधि समाप्त हो जाती है। वर्तमान



मामले में 15 दिनों की अवधि 14-10-1995 को समाप्त हो गई। इसलिए परिवाद दर्ज करने के लिए कार्यवाही का कारण 15-10-1995 से उत्पन्न होगा। एक महीने की अवधि की गणना के लिए उस दिन (15 अक्टूबर) अपवर्जित रखा जाना चाहिए। परिवाद 15 नवंबर, 1995 को दायर की गई। परिणाम यह होगा कि 15 नवंबर को दायर की गई परिवाद समय के भीतर है।

10. इसके बाद मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ को इकॉन एंट्री लिमिटेड बनाम रोम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट (2014) 11 एससीसी 769 में दी गई थी, जिसमें धारा 138 और सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि साकेत इंडिया लिमिटेड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि की सही प्रस्तावना निर्धारित करता है और यह अभिनिर्धारित किया है कि परिसीमा अवधि की गणना उस तिथि को छोड़कर की जानी चाहिए जिस पर कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 34, 37, 38, 41 और 42 में निम्नानुसार यह अभिनिर्धारित किया है:

34. चूंकि परिसीमा अधिनियम को एनआई अधिनियम पर लागू नहीं माना गया है, तरुण प्रसाद चटर्जी बनाम दीनानाथ शर्मा से समानता रखते हुए, जहां परिसीमा अधिनियम को लागू नहीं माना गया था, हम इस राय के हैं कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 की सहायता से वर्तमान मामले में यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एनआई अधिनियम की धारा 142 (बी) के तहत निर्धारित एक महीने की अवधि की गणना करते समय, अवधि की गणना उस दिनांक को अपवर्जित की जानी चाहिए जिस दिन कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ था। उत्तरवादी ओं के अधिवक्ता से इस बात पर सहमत होना संभव नहीं है कि धारा 138 में अलग-अलग स्थानों पर दो अलग-अलग शब्दों 'से' और 'का' का इस्तेमाल विधानमंडल द्वारा उक्त शब्दों के माध्यम से अलग-अलग अर्थ व्यक्त करने के आशय को दर्शाता है।

37. इंग्लैंड के हेल्सबरी के विधियों से सुसंगत अंश उद्धृत किए गए।

वे इस प्रकार हैं:---

"11. ... '168. प्रथम दिन का अपवर्जन ऐसे मामलों में सामान्य नियम यह है कि जिस दिन से कार्य या घटना की अवधि समाप्त होती है, उस दिन को उसके विरुद्ध नहीं गिना जाना चाहिए। यह सामान्य नियम इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होता है कि समय की परिसीमा किसी पक्ष के कार्य या विधि द्वारा लगाई गई है; इस प्रकार, जहां एक अवधि तय की जाती है जिसके भीतर आपराधिक अभियोजन या सिविल कार्रवाई शुरू की जा सकती है, वह दिन जिस दिन अपराध किया जाता है या कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, गणना में शामिल नहीं किया जाता है।"

38. इन परिस्थितियों में, वसंतलाल रणछोड़दास पटेल मामले में यह माना गया कि जिस दिन माल जब्त किया गया था, उसे धारा 110 की उपधारा (2) के तहत परिकल्पित सीमा अवधि की गणना में शामिल नहीं



किया जाना चाहिए और इसलिए नोटिस सीमा अवधि के भीतर जारी किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि परिसीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110(2) के तहत माल की जब्ती के छह महीने के भीतर नोटिस दिया जाना था। इसी तरह, एनआई अधिनियम की धारा 142(बी) के तहत, परिवाद उस दिनांक से एक महीने के भीतर की जानी चाहिए जिस दिन कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ। वसंतलाल रणछोड़दास पटेल में लिया गया दृष्टिकोण हमारे अनुमोदन से मेल खाता है।

41. हम इस स्तर पर यह नोट कर सकते हैं कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हिमाचल प्रदेश राज्य पर भरोसा किया, जहां तीन महीने की सीमा अवधि और आगे 30 दिनों की गणना के प्रश्न पर विचार करते हुए, जिसके भीतर पंचाट को चुनौती दायर की जानी है, जैसा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34(3) और उसके परंतुक में प्रावधान है, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12(1) और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 को ध्यान में रखते हुए, जिस दिन से ऐसी अवधि की गणना की जानी है उसे परिसीमा की गणना के लिए अपवर्जित किया जाता है। उत्तरवादी के अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 सीमा अधिनियम, 1963 को मध्यस्थता अधिनियम पर लागू करती है जबकि इसे एन.आई. अधिनियम पर लागू नहीं अभिनिर्धारित किया गया है और इसलिए यह निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा। हमने नोट किया है कि इस मामले में केवल परिसीमा अधिनियम की धारा 12(1) पर ही भरोसा नहीं किया गया है। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 9 पर भी भरोसा किया गया है। हालाँकि, चूँकि, इस मामले में हम सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 के आधार पर और अंग्रेजी निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जहाँ एक निश्चित तिथि से एक विशेष समय दिया गया है, जिसके भीतर कोई कार्य किया जाना है, उस तिथि के दिन को छोड़ दिया जाना है, इस पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है कि हिमाचल प्रदेश राज्य इस मामले पर लागू है या नहीं क्योंकि परिसीमा अधिनियम की धारा 12(1) पर इसमें भरोसा किया गया है। 42. इस मामले में शामिल कानून के प्रश्न पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने के बाद, प्रासंगिक निर्णयों के प्रकाश में, हम इस राय पर पहुँचे हैं कि साकेत कानून का सही प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। हम मानते हैं कि एक महीने की अवधि की गणना करने के उद्देश्य से, जो एन.आई. अधिनियम की धारा 142 (बी) के तहत निर्धारित है, अवधि की गणना उस तारीख को छोड़कर की जानी चाहिए जिस दिन कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था। हम अभिनिर्धारित करते हैं कि एसआईएल आयात, यूएसए सही विधि निर्धारित नहीं करता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय का कोई भी निर्णय जो इस न्यायालय द्वारा साकेत में लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण लेता है, जिसकी पुष्टि हम करते हैं, इस संदर्भ में शामिल प्रश्न पर सही विधि निर्धारित नहीं करता है। संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

11. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता 09.09.2022 को 30 दिनों की गणना के लिए बाहर रखने का हकदार है क्योंकि जिस दिनांक को कार्यवाही का कारण उत्पन्न होता है, उसे गणना में बाहर रखा गया है। इसी तरह, एनआई अधिनियम की धारा 105 के अनुसार 30 सार्वजनिक अवकाश की गणना में अनादर की



सूचना देने की अवधि को अपवर्जित किया जाना चाहिए। उत्तरवादी इस बात पर भी विवाद नहीं करता है कि 09.10.2022 रविवार था, ऐसे में इसे 30 दिनों की गिनती से बाहर रखा जाना चाहिए, इस प्रकार, नोटिस 10.10.2022 को दिया गया था जो 30 दिनों के भीतर है, इस प्रकार नोटिस विधि के तहत प्रदान की गई वैधानिक अवधि के भीतर दिया गया है, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि नोटिस 30 दिनों से अधिक समय के लिए दिया गया था, गलत, विकृत और विधि के विपरीत है और इस न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने योग्य है।

12. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है और मामले को विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर तय करने के लिए विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है। चूंकि पक्ष पहले ही इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं, इसलिए पक्षों को कोई नया नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। परिवादी तथा अभियुक्त 25.04.2025 को संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।



सही/-
(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य



प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

